© IJCIRAS | ISSN (O) - 2581-5334
December 2019 | Vol. 2 Issue. 7

# भारत में बैंकिंग व्यवसाय – एक विश्लेषण

**Dr. Rajesh Maurya, Prof. J P Mittal**
*Government Nehru College*
*Sabalgarh*

## शोधसार (Abstract)

बैंक वे वित्तीय संस्थाऐं होती हैं जो लोगों से मॉग या समय जमा को स्वीकार करके समय-समय पर देश के नागरिकों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं। भारतीय बैंकिंग संरचना में अनेक बैंकों को शामिल किया गया हैं जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक, निजी बैंक तथा छोटे व भुगतान बैंक आदि। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक या सरकारी बैंक होता हैं जिसका कार्य अपने अधीन बैंकों पर निगरानी व नियंत्रण रखना, नोटों का निर्गमन व पुर्नःनिर्गमन करना, अपने अधीन बैंकों को बैंक दर नीति के माध्यम से ऋण प्रदान तथा सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह व परामर्श प्रदान करना आदि हैं जबकि वाणिज्य वैंक पूर्ण रूप से लाभ के आधार पर संचालित किये गये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में ऐसी बैंकों को शामिल किया गया हैं जिनका सन १९६९ एवं १९८० में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बैंक देश के कुल बैंकिंग व्यवसाय में ७५ः से अधिक का हिस्सा रखते हैं।(३१) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण वित्तीय समावेशन हेतु गॉव के भूमिहीन, कृषक मजदूर, सीमांत किसानों व गॉव के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी हैं। इनका गठन तीन निकायों जैसे - प्रायोजित बैंक, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया गया हैं। जिसमें केन्द्र सरकार का ५०ःए प्रायोजित बैंक का ३५ः और राज्य सरकार का १५ः हिस्सा शामिल हैं।(३०)

विदेशी बैंक वे बैंक होते हैं जिनका मुख्य कार्यालय विदेशों में होता हैं किन्तु वह भारत में एक शाखा कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। नवम्बर २०१८ के अनुसार भारत में ४५ विदेशी बैंक अपनी २८६ शाखाओं के साथ सम्पूर्ण भारत में कार्यरत हैं।(३३)

भारत में निजी बैंकों की नीव सन् १९९१ में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अन्तर्गत रखी गयी थी। इसके अन्तर्गत आई.सी. आई., सी.आई. बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक आदि शामिल हैं।

छोटे वित्तीय बैंक तथा भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नये मॉडल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार - ''छोटे वित्त बैंक वे बैंक हैं जिन्हें आर.बी.आई. से लायसेंस प्राप्त हैं तथा जो जमा व उधार संबंधी कार्य कर सकते हैं(४१) जबकि भुगतान बैंक वे बैंक हैं जो प्रतिबंध जमा को स्वीकार करते हैं जो वर्तमान में प्रति ग्राहक १,००,००० तक सीमित हैं।(४३) ये बैंक ऋण एवं क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते लेकिन ए.टी.एम. (।ज्ड), नेट बैंकिंग, और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाऐं प्रदान कर सकते हैं।

यदपि वर्तमान में भारतीय बैंकों की स्थिति दयनीय हैं लेकिन फिर भी देश के सामाजिक-आर्थिक-विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं

**की वर्ड्स-** भारत में बैंकिंग व्यवसाय (बैंकिंग का अर्थ एवं परिभाषायेंए ऐतिहासिक परिपेक्ष्यए बैंकिंग संरचना

### प्रस्तावना

किसी भी देश के संदर्भ में बैंक वित्तीय संस्थान की दृष्टि से एक देश की आधार-शिला या आधार स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं। यदि यह कहा जाये कि बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं तो इसमें कोई अतिश्यौक्ति नहीं होगी। बैंक देश के लोगों की जमा को स्वीकार करके समयानुसार भुगतान करने का कार्य करती हैं। ये संस्थान न केवल धन के आदान-प्रदान में संलग्न हैं बल्कि लोगों के बीच बचत करने की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि बचत ही वह कारक हैं जो पूॅजी निर्माण को उत्पन्न करने में सहयोग करता हैं। अर्थव्यवस्था में जितने भी कारक जैसेः- उद्योग-धंधे, निवेश, उत्पादन की मात्रा एवं रोजगार आदि पूॅजी निर्माण के द्वारा ही संचालित एवं कार्यान्वित होते हैं।

बैंकों को कार्य के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया हैं जैसेः- वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, तथा केन्द्रीय बैंक आदि। वाणिज्य बैंक वे बैंक होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता से जुड़े रहते हैं। लोगो की जमा पूँजी को स्वीकार करना, समय-समय पर भुगतान करना तथा लोगों की उपलब्ध जमा पूँजी के आधार पर ऋण देना इत्यादि इनका काम हैं जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश के पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से दूर-दराज स्थित गॉव के लोगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से स्थापित किये गये हैं। भूमि विकास बैंक, जिनकी स्थापना राज्य स्तर पर की गयी थी, का प्रमुख कार्य कृषि विकास या कृषि से संबंधित कार्यो हेतु गरीब व सीमाँत किसानों को ऋण उपलब्ध कराना हैं। जब हम केन्द्रीय बैंक की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य एक ऐसा बैंक हैं जो प्रत्येक देश में केवल एक ही पाया जाता हैं जिसका कार्य सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को स्थिरता प्रदान करना हैं। ये एक प्रकार से देश की समस्त बैंकों का राजा होता हैं जो कि अपने अधीनस्थ बैंकों (वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक) पर वित्तीय मामलों के संबंध में अधिकार एवं नियंत्रण संबंधी कार्यों में शामिल होता हैं। बैंकों की एक निश्चित जमा पूँजी को अपने पास रखना, अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण की प्रक्रिया को बनाये रखना, सरकार को समय-समय पर ऋण उपलब्ध कराना तथा वित्तीय मामलों में सलाह प्रदान करना आदि केन्द्रीय बैंक के कार्य हैं। भारत में स्थित केन्द्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक हैं।

आधुनिक आर्थिक प्रणाली में बैंके देश के आर्थिक विकास हेतु अपनी अहम भूमिका अदा कर रही हैं। बचत के माध्यम से पूँजी निर्माण को बढ़ावा देकर विनियोग की मात्रा को प्रोत्साहित कर रही हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग-धंधे प्रगति के सोपानों तक पहुँच सके। देश के पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह को संचालित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे रही हैं। उद्योगपतियों को वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चा माल क्रय करने के लिये ऋण उपलब्ध करा रही हैं तथा देश के पिछड़े हुये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आर्थिक विकास हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराके इन ग्रामीणवासियों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। जिससे देश की अर्थव्यवस्था में व्यापार एवं उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ हैं और पूर्व की तुलना में देश की विकास दर में वृद्धि हुयी हैं।

**एतिहासिक परिपेक्ष्यः-** विश्व स्तर पर बैंक शब्द की उत्पत्ति के प्रमाण यूरोपीयन देश इटली से प्राप्त हुये माने जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि प्राचीन काल में इटली के व्यापारी बैंचों पर बैठकर मुद्रा विनिमय से संबंधित हिसाब-किताब का कार्य किया करते थे और जब किसी व्यापारी का व्यापार बंद हो जाता था तो उस बैंच को तोड़ दिया जाता था। बाद में यही बैंच शब्द इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि इस शब्द ने बैंच के स्थान पर बैंक शब्द का रूप धारण कर लिया था। आज हम जिस बैंक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वह इसी प्राचीन अवधारणा का परिणाम हैं।

इटली के दृष्टिकोण से सबसे पहला और प्रसिद्ध बैंक - **''मेडिसीन बैंक था** जिसकी स्थापना १३९७ में **जियोवानी डी बिक्सी डी मेडिसी** द्वारा स्थापित किया गया था।(१) इसके बाद - **''बैंको डि सैन जियोर्जियो (सैंटगार्ज) का बैंक** १४०७ में जेनोआ इटली में स्थापित किया गया था।(२)

बैंकिंग इतिहास में १७ वी एवं १८ वी शताब्दीयॉ वह अवधियॉ थी जिसमें ऑशिंक स्तर पर बैंकिंग पद्धतियों तथा बैंक नोटों का मुददा उभरकर सामने आया था। जिसके अन्तर्गत व्यापारियों तथा सुनारों ने मुद्रा लेनदेन का कार्य आरंभ कर दिया था - **''उस समय व्यापारियों ने लंदन के सुनारों के साथ** अपना सोना एकत्रित करना शुरू कर दिया। सुनार द्वारा ली गई कीमती धातु के बदले में उन्होंने रसीदें जारी की जो धातु की मात्रा तथा शुद्धता प्रमाणित करती थी। यह एक प्रकार से सुनार के पास जमानत के रूप में रखी जाती थी धीरे-धीरे जमानत के रूप में रखी गयी धातु के आधार पर सुनारों ने ऋण देना प्रारंभ कर दिया था और इसी ऋण देने की प्रक्रिया के कारण ही आधुनिक बैंकिंग प्रथाओं का विकास हुआ। सुनार द्वारा ऋण प्रदान करने हेतु प्रॉमिसरी नोटो (बैंक में विकसित किये गये नोट) का प्रचलन बढ़ा था जिसके बदले सुनारों ने ब्याज लिया था''(३) प्रॉमिसरी नोटो के प्रचलन के कारण लोगों द्वारा उनकी मॉग की जाने लगी क्योंकि यह लम्बी अवधि के लिये प्राप्त किये गये ऋणों को अदा करने के योग्य हो गये थे। यह एक प्रकार से ऑशिंक रिजर्व बैंकिंग का प्रारंभिक रूप था - **''प्रॉमिसरी नोट एक असायन** करने योग्य साधन के रूप में विकसित किये गये जो सुनार के वादे के भुगतान द्वारा समर्पित धन के सुरक्षित और सुविधाजनक रूप में प्रसारित हो सकते थे।(४) जिससे सुनार कम जोखिम के साथ अग्रिम ऋण प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार लंदन के सुनार क्रेडिट के आधार पर नया पैसा बनाकर बैंकिंग के अग्रदूत बन गये थे।

इंग्लैण्ड के दृष्टिकोण से - **''क्रेडिट बैंक ऑफ इंग्लैण्ड** ने सबसे पहले १६९५ में बैंक नोटस के स्थायी मुददे को शुरू किया था''(५)

सन १७२८ में **रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड** ने पहली ओवर ड्राफ्ट सुविधा की स्थापना की थी।(६)

१९ वी शताब्दी की शुरूआत तक विश्व में कई बैंकों को अनुमति देने के लिये लंदन में एक **बैंकर्स क्लीयरिंग हाउस की** स्थापना की गयी थी। जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व के देशों में जगह-जगह बैंकों की स्थापना शुरू हो गयी थी। इस प्रकार बैंकों का कार्य आरंभ हुआ।

भारत के संदर्भ में बैंकिंग की उत्पत्ति या आरंभ को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया हैं जैसेः- प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत, स्वतंत्रता से पूर्व भारत, स्वतंत्रता के बाद का भारत और आर्थिक सुधारों का भारत **(१९९१ से वर्तमान तक)** आदि।

१. **प्राचीन भारत** :- प्राचीन भारतीय वेदशास्त्रों के अनुसार बैंकिंग इतिहास से संबंधित प्रमाणों का उल्लेख भारतीय वेदों (२०००-१४००) प्राप्त होता हैं। इसके अन्तर्गत सूदखोरी की अवधारणा, जो कि बैंकिंग के इतिहास से संबंधित हैं, का उल्लेख मिलता हैं। **फ्रेड गोथेल (थ्तमक ळवजजीमपस) के अनुसार** - "प्राचीन काल में कुसीदीन शब्द का अनुवाद सूदखोरी के रूप में किया गया था। सूत्र बताते हैं कि ७०० से १०० ई. पूर्व और जातक ६०० से ४०० ई. पू. में भी सूदखोरी का विवरण मिलता हैं। जिसकी भारतीय ब्राह्मणों, क्षत्रिय, गुरू-वशिष्ट जैसे लोगों ने अपने कठोर शब्दों में निंदा की थी लेकिन आगे जाकर अर्थात दूसरी शताब्दी में सूदखोरी अधिक स्वीकार्य हो गयी थी।(७) सूदखोरी के प्रमाण प्राचीन धर्मग्रन्थ मनुस्मृति में भी मिलते हैं। **मनुस्मृति के अनुसार** - "उस समय सूदखोरी जीविका चलाने तथा धन प्राप्त करने का एक स्वीकार्य साधन था।(८)

भारतीय कूटनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्र के प्रकाँण्ड विद्वान कौटिल्य ने अपनी पुस्तक - **"अर्थशास्त्र में ऋण कार्यों** के अस्तित्व का उल्लेख किया था जिसे उस समय मृण्मय काल कहा जाता था।(९, १०)

२. **मध्ययुगीन भारतः**- मध्यकालीन भारत अर्थात मुगल युग में ऋण के कार्यों और उसका उपयोग आदि का उल्लेख मिलता हैं जिसे इस युग में दास्तव कहा जाता था। **भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार** - "मुगाल काल में दो प्रकार के ऋणों (दास्तव) को दर्ज किया गया था। पहला - **दस्तावेज-ए-इन्दुललतलब,** तथा दूसरा - **दास्तववेज-ए-मियादी** इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। इस समय शाही खजाने द्वारा भुगतान आदेशों का उपयोग, जिन्हें बैरेट कहा जाता था, को भी दर्ज किया गया था। विदेशों में विनिमय के बिल जारी करने के लिये भारतीय बैंकरों के दस्तावेज भी हैं। इस प्रकार का ऋण साधन, हुडडीयॉ का विकास भी इस अवधि के दौरान हुआ था।(१०)

३. **स्वतंत्रता से पूर्व का भारतः**- यदि वास्तविक रूप देखा जाये तो भारत में विधिवत बैंकिंग की शुरूआत उस समय से मानी जाती हैं जब से अँग्रेजों ने भारत की सत्ता संभालना प्रारंभ किया था और उनके काल में अनेक बैंक स्थापित किये गये थे। लेकिन आधुनिक युग के अनुसार बैंकों की स्थापना १८ वी शताब्दी के अंतिम दशक से मानी जाती हैं। इस दृष्टि से **सन १७७० में बैंक ऑफ हिन्दुस्तान** की स्थापना की गयी थी जो कि भारत का पहला बैंक था लेकिन यह १८२९ से १८३२ तक की अवधि में विफल हो गया था।(११, १२) इसके बाद इस दशक में कई और बैंक स्थापित हुये थे जैसे- १८०६ में बैंक ऑफ बंगाल, १८९४ में पंजाब बैंक, १८६५ में इलाहाबाद बैंक, १८४० में बैंक ऑफ बॉम्बे, १८४५ में यूनियन बैंक, १८६३ में बैंक ऑफ इंडिया तथा १८६० में विदेशी बैंक और कॉम्पटेयर डी एसकॉम्पट डी पेरिस आदि स्थापित किये गये थे।

सन १८०६ में स्थापित किया गया बैंक ऑफ बंगाल का नाम पूर्व में भारतीय स्टेट बैंक था जिसे सन १८०९ में बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था जो कि भारत का सबसे पुराना एवं बड़ा बैंक कहा जाता हैं। **सन १९२१ में** बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एवं बैंक ऑफ मद्रास उक्त तीनों का विलय करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बाद में यही बैंक अर्थात १९५५ में भारतीय स्टेट बैंक बन गया था जो कि आज भी अस्तित्व में हैं और भारत का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला बैंक बन गया हैं।(१३,१४) ये तीनों बैंक अर्थात बैकं ऑफ बंगाल, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसीडेन्सी बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं। जिनकी स्थापना - **"भारत में स्थित ब्रिट्रिश ईस्ट इंडिया** कंपनी चार्टड के तहत की गयी थी।(१५)

सन **१८४५** में स्थापित किया गया यूनियन बैंक दिवालिया होने के कारण सन १८४८ में विफल हो गया था। ऐसी स्थिति में इस बैंक ने अपने ग्राहकों का लाभांस वापिस करने के लिये नये पैसों का इस्तेमाल किया था(१६) लेकिन १८६५ में स्थापित किया गया इलाहाबाद बैंक अभी भी कार्य कर रहा हैं। यह भारत में संयुक्त स्टॉक बैंक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस बैंक को यह सम्मान सन १८६३ में बैंक ऑफ

इंडिया द्वारा प्राप्त हुआ था परन्तु कुछ समय बाद यह भी विफल हो गया था जिसकी कुछ देनदारियाँ शिमला के एलाइंस बैंक में स्थानांतरित हो गयी थी।

भारतीय बैंकिंग इतिहास में सन १८६० का दशक वह दशक था जिसके अन्तर्गत विदेशी बैंक दिखाई देने लगे थे और यह बैंक ग्रिडलेज बैंक था **जिसमें अपनी पहली शाखा सन १८६४ में** कलकत्ता में खोली थी।''**(१७)**

**''सन १९३५ में** हिल्टन यंग की सिफारिशों के आधार पर भारत का केन्द्रीय बैंक के नाम से जाने वाला बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी थी। इसने औपचारिक रूप से तत्कालीन इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इन जिम्मेदारियों को संभाला था जिसका राष्ट्रीयकरण सन १९४९ अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के बाद किया गया था।''**(१८)**

४. **स्वतंत्रता के बाद का भारतः–** सन १९४७ में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित था। बेकारी, भूखमरी तथा बेरोजगारी जैसी समस्याऐं व्याप्त थी। बैंकिंग की दृष्टि से तो भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। ग्रामीण जनता पूर्ण रूप से गॉव के साहूकार एवं जमीदारों पर निर्भर थी। उन्हें अपनी छोटी-छोटी वित्त संबंधी जरूरतों के लिये इन पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिये भारत सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिये सर्वप्रथम केन्द्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) का सन १९४९ में राष्ट्रीयकरण किया ताकि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के साथ पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जा सके। इसके अलावा निजी स्वामित्व के तहत स्वदेशी बैंकों का समर्थन करने वाले नेताओं जैसे – **''लाला लाजपत राय, सरदार दयाल सिंह मजीठिया जैसे लोगों ने** स्थानीय व्यापारियों एवं राजनैतिक लोगों को भारतीय समुदाय के लिये बैंक स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ केनरा, सैन्ट्रल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इंडियन जैसे बैंकों की स्थापना हुयी थी।**(१८)**

भारत के गरीब, पिछड़े एवं ग्रामीण जनता को वित्तीय सुविधा मुहैया कराने के लिये उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने – **''१९ जुलाई, १९६९ को १४ वाणिज्यिक बैंकों** का राष्ट्रीयकरण किया जिसके तहत निम्नलिखित बैंक राष्ट्रीयकृत किये गये जैसेः- पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ केनरा, बैंक ऑफ बडौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड वाणिज्य बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक आदि।**(१९)**

**अप्रैल, १९८० में** भारत सरकार द्वारा ६ और वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनके नाम आन्ध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि।**''(१९)**

भारतीय स्वतंत्रता के बाद वित्तीय दृष्टिकोण से भारत का जो हिस्सा सबसे अधिक पिछड़ा हुआ था तो वह ग्रामीण क्षेत्र था। गॉव के गरीब, भूमिहीन, सीमॉत तथा कमजोर वर्ग (ब्धैज्ध्ळ्ठब) के लोग अभी भी वित्तीय पहुँच से काफी दूर थे। उनकी छोटी-छोटी वित्त संबंधी जरूरतें पूर्ण नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में – **''२ अक्टूबर, १९७५ में** नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था**''(१९)** ताकि उनकी वित्त संबंधी आवश्यकताऐं पूर्ण हो सके। इसके अलावा भारत के कुछ और पिछड़े क्षेत्र जैसेः- आवास, उद्योग, विदेशी व्यापार तथा कृषि से संबंधित कार्य आदि भी थे जिनके विकास हेतु और बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की गयी थी जैसेः- **''१९८२ में नाबार्ड एक्जिम बैंक, १९८८ में एन.एच.बी., तथा १९९० में सिडवी (ष्क्ठप्) आदि।(१९)**

इन बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के कारण भारतीय वित्तीय एवं बैंकिंग पद्धति में सुधार हुआ। लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में धन मिलना प्रारंभ हुआ। दिन-प्रतिदिन उद्योगों की प्रगति में सुधार हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था उच्चस्तर पर पहुँच गयी।

५. **आर्थिक सुधारों का भारतः–** सन १९९१ में उस समय के प्रधानमंत्री श्री पी.व्ही. नरसिंहराव की सरकार के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में और अधिक विकास हेतु आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी जिसके अन्तर्गत वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण जैसी नीतियॉ अमल में लायी गयी थी। जिससे बैंकों की विकास प्रक्रिया में और अधिक उल्लेखनीय वृद्धि हुयी थी। इस अवधि में बैंकिंग विकास हेतु जो सर्वप्रमुख निर्णय लिया गया था वह निजी क्षेत्रों के बैंक एवं विदेशी बैंकों को अर्थव्यवस्था में प्रवेश की अनुमति प्रदान करना रहा

था। इसके अलावा बैंकों की वित्तीय स्थिरता तथा लाभप्रदाता में सुधार करने के लिये भारत सरकार ने नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जिसने अपनी सिफारिशे निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत की थी।

- भारतीय बैंकों को प्रतिस्पर्धी एवं वित्तीय स्थिरता के अनुकूल बनाना।
- भारत में विदेशी बैकों को अपनी शाखाऐं खोलने की अनुमति प्रदान करना।
- भारतीय बैंकिंग राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में और सुधार करना।
- भारतीय बैंकिंग पद्धति की रूढ़िवादी एवं पारम्परिक कार्य प्रणाली में सुधार कर आधुनिक बैंकिंग पद्धति की प्रक्रियाओं को अपनाना आदि।

नरसिम्हन समिति की इन सिफारिशों के बाद – **"भारतीय रिजर्व बैंक** ने १० निजी संस्थाओं को देश में बैंक स्थापित करने के लिये लायसेंस प्रदान किये थे। जिसके तहत आई.सी.आई.सी.आई (प्ब्ब्), एच.डी.एफ.सी.(भ्क्थ्ब्), एक्सिस बैंक (।गपे ठंदा), इनडसन्ड बैंक (प्दकनेपदक ठंदा) आदि का गठन किया गया था"**(१६)**

सन १९९८ में भारतीय रिजर्ब बैंक ने दो और नये बैंकों जैसे- **"कोटक महिन्द्रा फायनेंस (२००१) तथा यस बैंक (२००४)** को लायसेंस दिये थे।**(१६)**

भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा लायसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत **वर्ष २०१५ में आई.डी.एफ.सी.(प्क्थ्ब्) तथा बंधन जैसे बैकों का उदय हुआ था।(१६)**

वर्तमान में भारत में ८८ अनुसूचित वाणिज्य बैंक, २७ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारत सरकार के साथ हिस्सेदारी रखने वाले बैंक) २९ निजी क्षेत्र के बैंक हैं – **"जिसके पास ५३००० शाखाओं का संयुक्त नेटवर्क और १७००० से अधिक ए.टी.एम.(।ज्ड) हैं।(१८)**

एक रिपोर्ट के अनुसार – **"सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग उद्योग की कुल सम्पत्ति का ७५ः से अधिक का हिस्सा रखते हैं।(१८)**

**बैंक का अर्थ तथा परिभाषाऐं**

हमारे दिमाग में बैंक शब्द का नाम सुनते ही एक ऐसी छवि बन जाती हैं कि यह धन जमा करने तथा ऋण देने वाली संस्था हैं परन्तु यह सत्य नहीं हैं। बैंके धन जमा एवं ऋण प्रदान करने के अलावा कई अन्य कार्य जैसेः- चैक का भुगतान, डिमॉड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड सेवाऐं, ए.टी.एम सेवाएं, प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय आदि कार्य भी करती हैं। दूसरे शब्दों में - "बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो लोगों की समय व मॉग जमा को स्वीकार करने, ऋण बनाने, प्रतिभूतियों का निवेश करके धन एकत्रित करने हेतु सरकार द्वारा लायसेंस प्रदान किये जाते हैं। यह विशेष रूप से चार्ज तथा भुगतान की गयी ब्याज दरों के अंतर से लाभ अर्जित करते हैं।

बैंक को एक व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता हैं किन्तु यह किसी उत्पाद का निर्माण नहीं करते बल्कि वे कुछ सेवाऐं जैसेः- आवास ऋण, कार ऋण, चेंकिंग खाते, शैक्षणिक ऋण, क्रेडिट कार्ड सेवाऐं तथा जमा प्रमाण पत्र आदि बेचने का कार्य करती हैं।

बैंकों का निर्माण देश के नागरिकों की जमा पूँजी को सुरक्षित रखने तथा उक्त जमा पूँजी के आधार पर अतिरिक्त धन या ब्याज प्राप्त करने हेतु किया गया हैं। ब्याज वह धनराशि होती हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को दी गयी धनराशि के बदले उपहार स्वरूप प्राप्त होती हैं। बैंके विश्व के लगभग सभी देशों में पायी जाती हैं लेकिन वह अलग-अलग देशों के कानूनों के अनुसार संचालित होती हैं।

बैंक के अंतर्गत ग्राहक और बैंक कर्मचारियों के बीच विशिष्ट संबंध पाया जाता हैं। बैंक कर्मचारी बैंकिंग विकास हेतु जनता से सीधे व्यवहार करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग बैंक में खाता खोल सके क्योंकि बैंक द्वारा ब्याज के आधार पर अन्य व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया इन्ही खातों पर निर्भर करती हैं। लोगों द्वारा खोले गये खाते आम लोगों के बीच न केवल बचत की मात्रा को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि बैंकों की साख सृजन प्रक्रिया में भी मदद प्रदान करते हैं।

वर्तमान में बैंकों का महत्व इतना अधिक बढ़ चुका हैं कि बैक की परिभाषा को कुछ निश्चित शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं हैं इसलिये बैंक की परिभाषा को कार्य पद्धति और नियम व अधिनियम के आधार पर अनेक भागों में विभाजित किया गया हैं।

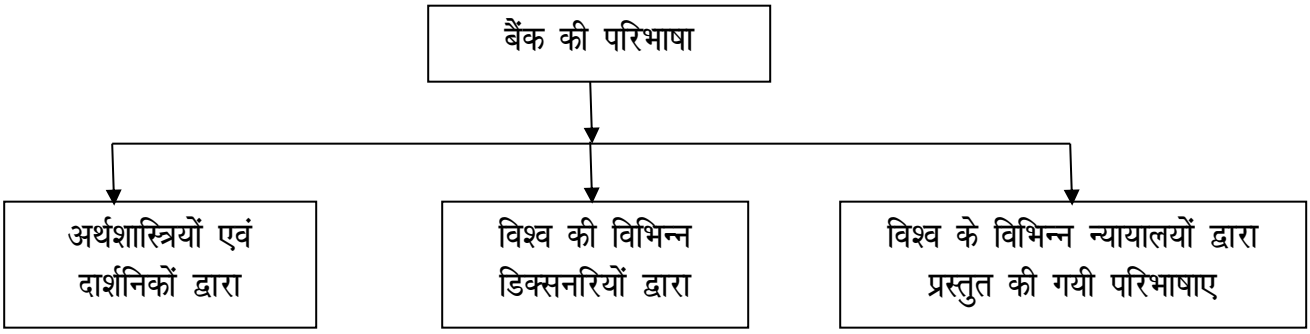


- **अर्थशास्त्रियों एवं दार्शनिकों द्वाराः-** विश्व के विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं दार्शनिकों द्वारा दी गयी परिभाषाऐं निम्नलिखित हैं।

**केंट (Kent) के अनुसारः-** "केंट ने अपनी परिभाषा के अन्तर्गत बैंक को एक संगठन के रूप में परिभाषित किया हैं जिसका प्रमुख संचालन आम जनता के अस्थायी रूप से निष्क्रिय धन के संचय से संबंधित हैं जो व्यय के लिये दूसरों को आगे बढ़ाने के उददेश्य से कार्य करते हैं।(२०)

**सेयेट (Sayets) के अनुसार** - "साधारण बैंकिंग व्यवसाय में बैंक जमा के लिये नगदी बदलना और नगदी के लिये बैंक जमा आदि शामिल हैं। बैंक जमा को एक व्यक्ति या निगम से दूसरे को स्थानांतरित करना, विनिमय के बिलों के बदले बैंक जमा देना, सरकारी बॉड सुरक्षित या असुरक्षित बादे आदि शामिल हैं।"(२०)

**क्रॉथर (Crowther) के अनुसार-** "एक बैंक अपने तथा अन्य लोगों के लिये एक डीलर हैं।"(२१)

**जॉन हैरी (Jhon Harry) के अनुसार-** "बैंक एक आर्थिक संस्थान हैं जिसका मुख्य उददेश्य पैसे और क्रेडिट साधन के आदान-प्रदान के माध्यम से लाभ कमाना हैं।"(२१)

**आर. पी. केन्ट(R. P. Kent) के अनुसार-** "एक बैंक एक संस्था हैं जिसका प्रमुख कार्य लोगों के बिना सोचे समझे धन एकत्रित करना और दूसरे लोगों को उधार देना शामिल हैं।"(२१)

**आर.एस.सेयर्स (R. S. Sayers) के अनुसार** - "बैंक वे संस्थान होते हैं जिनके ऋणों को आमतौर पर अन्य लोगों के निपटान में स्वीकार किया जाता हैं।"(२१)

**केयरक्रॉस (Cairncross)** के अनुसार - ''एक बैंक ऋण एवं ऋण डीलर के रूप में एक वित्तीय मध्यस्थ हैं।"(२१)

- **विश्व की विभिन्न डिक्सनरियों द्वारा :-** विश्व की विभिन्न डिक्सनरियों ने बैंक की परिभाषा को अलग-अलग रूप में इस प्रकार दी हैं।

**इम्पीरियल डिक्सनरी (Imperial Dictionary) के अनुसार** - "एक बैंक एक प्रतिष्ठान हैं जिसमें जमा, कस्टडी तथा पैसे जारी करता हैं और साथ ही उधार देने एवं बिलों में छूट देने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषण के प्रसारण की सुविधा के लिये कार्य करता हैं।"(२१)

**चैम्बर डिक्सनरी के अनुसार** - "चेम्बर की २०वी शताब्दी की डिक्सनरी एक बैंक को धन रखने, उधार देने और आदान-प्रदान करने आदि के लिये एक संस्था के रूप में परिभाषित करती हैं।"(२०)

**बिजनिस डिक्सनरी के अनुसार** - "बैंक एक सरकार द्वारा जमा को स्वीकार करने, ब्याज का भुगतान करने, स्पष्ट चैक, ऋण देने, वित्तीय मध्यस्त के रूप में काम करने और अपने ग्राहकों को अन्य वित्तीय सेवाऐं प्रदान करने के लिये अधिकृत एक प्रतिष्ठान हैं।"(२२)

**ए.टी. देव डिक्सनरी (।ण ज्ण क्मअ क्पबजपवदंतल) के अनुसार** – "बैंक ऐसी संस्था हैं जहॉ धन प्राप्त करने के लिये पैसे मिलते हैं और मॉगने पर वापस कर दिये जाते हैं।"(२१)

**समसाद डिक्सनरी (ैउेंक क्पबजपवदंतल) के अनुसार** – "एक बैंक धन की प्राप्ति और निवेश के लिये एक संस्था हैं।"(२१)

**डिक्सनरी ऑफ बैंकिंग एण्ड फायनैंस के अनुसार** – "एक बैंक राज्य या संघीय सरकार द्वारा चार्टड एक संगठन हैं जिसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

१. (।) डिमॉड डिपोजिट प्राप्त करना और उनके खिलाफ तैयार ग्राहकों के चैक का भुगतान करना।

२. (।) समय जमा का भुगतान करना और उसमें ब्याज का भुगतान करना शामिल हैं।

३. (ठ) नोटो को छूट देने के लिये ऋण बनाये तथा सरकार या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करना।

४. (ब) चैक, ड्राफ्ट, नोट एकत्र करना।

५. (क) ड्राफ्ट और कैशियर के चैक जारी करना।

६. (म) जमाकर्ताओं की जांच को प्रमाणित करना।

७. (थ) जब चार्टरिंग सरकार द्वारा अधिकृत हो, यह एक विवादस्पदा क्षमता में कार्य करती हैं।

- **विश्व के विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत की गयी परिभाषाऐं** :– बैंक को कानूनी रूप से परिभाषित करने के लिये कुछ विश्व के न्यायालयों ने अपने-अपने कानूनों के अनुसार बैंक की परिभाषाऐं इस प्रकार प्रदान की हैं।

**यूनाइटेड स्टेटस सुप्रीम कोर्ट (ऑस्टेन, १८९६) के अनुसार**– "एक बैंक एक संस्था हैं जिसे प्रॉमिसरी नोट के साथ शामिल किया गया हैं, जिसका उददेश्य पैसे के रूप में प्रसारित करना हैं। यह सामान्य जमा पर दूसरे के पैसे प्राप्त करने के लिये तथा एक संयुक्त फण्ड बनाने के लिये इसका उपयोग किया जाता हैं। संस्था अपने स्वयं के लाभ के लिये, अस्थायी ऋण तथा छूट देने के साथ या अधिक उददेश्यों के लिये नोटस, विनिमय, सिक्का, क्रेडिट एवं घरेलू बिलों के लिये या इन दोनों शक्तियों के साथ और विशेषाधिकारों के साथ प्राप्त करने के लिये ये संस्थान उपर्युक्त होते हैं।"(२३)

**रि-शील्ड स्टेटस, आयरिश रिपोर्ट (१९०१) के अनुसार** – "बैंकर का व्यवसाय धन जमा करना हैं जिसे वह अपने उधार के लिये लाभ का उपयोग कर सकता हैं।"(२४)

**स्विस बैंक कॉर्पोरेशन के अनुसार** – "सन १९२१ में जोआकिमसन के मामले में न्यायमूर्ति **एटकिन** ने लिखा हैं कि – "बैंक धन प्राप्त करने और अपने ग्राहक के खाते में बिल जमा करने का कार्य करता हैं। इसलिये प्राप्त की गयी कार्यवाही ग्राहक के लिये भरोसेमंद नहीं होती हैं, लेकिन बैंक आय को अदा करता हैं और उन्हें चुकाने का वचन देता हैं। चुकाने का वादा उस बैंक की शाखा में चुकाने का होता हैं जहॉ खाता खोला जाता हैं और बैंकिंग घण्टों के दौरान इसमें लिखित रूप से देय राशि के किसी भी हिस्से को चुकाने का वादा शामिल होता हैं। बैंककर्मी मॉग के अलावा चालू-खाते के संबंध में किसी ग्राहक को भुगतान नहीं करते हैं।"(२५)

उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि बैंक एक संस्था या व्यवसाय हैं जो लोगों की मॉग एवं समय जमा स्वीकार करने, ऋण प्रदान करने, नोटों का सृजन करने, डिमॉग ड्राफ्ट, चैक का भुगतान करने, क्रेडिट कार्ड सेवाएं तथा ए.टी.एम. सेवाएं आदि प्रदान करने का कार्य करती हैं।

**भारत की बैंकिंग संरचना** :– यदि भारतीय बैंकिंग इतिहास पर दृष्टि डाली जाये तो यह स्पष्ट होता हैं कि भारत में बैंकों की शुरूआत १८वी शताब्दी में हुयी थी। इस शताब्दी में बैंकों का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। समाज का एक विशेष वर्ग अर्थात व्यापारियों द्वारा ही अपना

हिसाब-किताब बनाये रखने के लिये बैंकों का इस्तेमाल करते थे। भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व बैंकिंग व्यवसाय प्रेसीडेंसी बैंकों के नाम से जाना जाता था जो कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जिसे बाद में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया।

भारतीय औद्योगिक अवधि के आरंभिक दिनों में निजी स्वामित्व तथा अस्थिर कार्य का माहौल देखा गया था। बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक स्वामित्व एवं जवाबदेही के प्रति प्रमुख कदम सन १९६९ एवं १९८० अर्थात राष्ट्रीयकरण की अवधि में देखा गया था जिसने भारतीय बैंकिंग पद्धति का चेहरा ही बदल दिया था। सन १९९१ में अपनायी गयी उदारीकरण की प्रक्रिया ने बैंकिंग क्षेत्र में और बदलाव देखे तथा भारतीय बैंकिंग पद्धति अपने प्रगति के उच्च शिखर पर पहुँच गयी थी जो कि आज तक विद्यमान हैं।

बैंक एक प्रकार की वित्तीय संस्थान हैं जिन्होंने कई दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत एवं पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका अदा की हैं इसलिये भारतीय बैंकिंग व्यवसाय को आमतौर पर दो भागों में बॉटा गया हैं। पहला- संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत भारत की उच्च स्तर की बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, विशेष वित्तीय संस्थान जैसेः- आई.डी. बी. आई, आई. सी. आई सी. आई, आई.एफ.सी. आदि शामिल की गयी हैं जबकि असंगठित क्षेत्र अर्थात गैर-अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम १९३४ की दूसरी सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसमें ५ लाख रूपये से कम आरक्षित पूँजीवाले बैंक आते हैं। ये बैंक किसी भी परिस्थितियों में आर.बी.आई. से ऋण लेने के हकदार नहीं हैं।

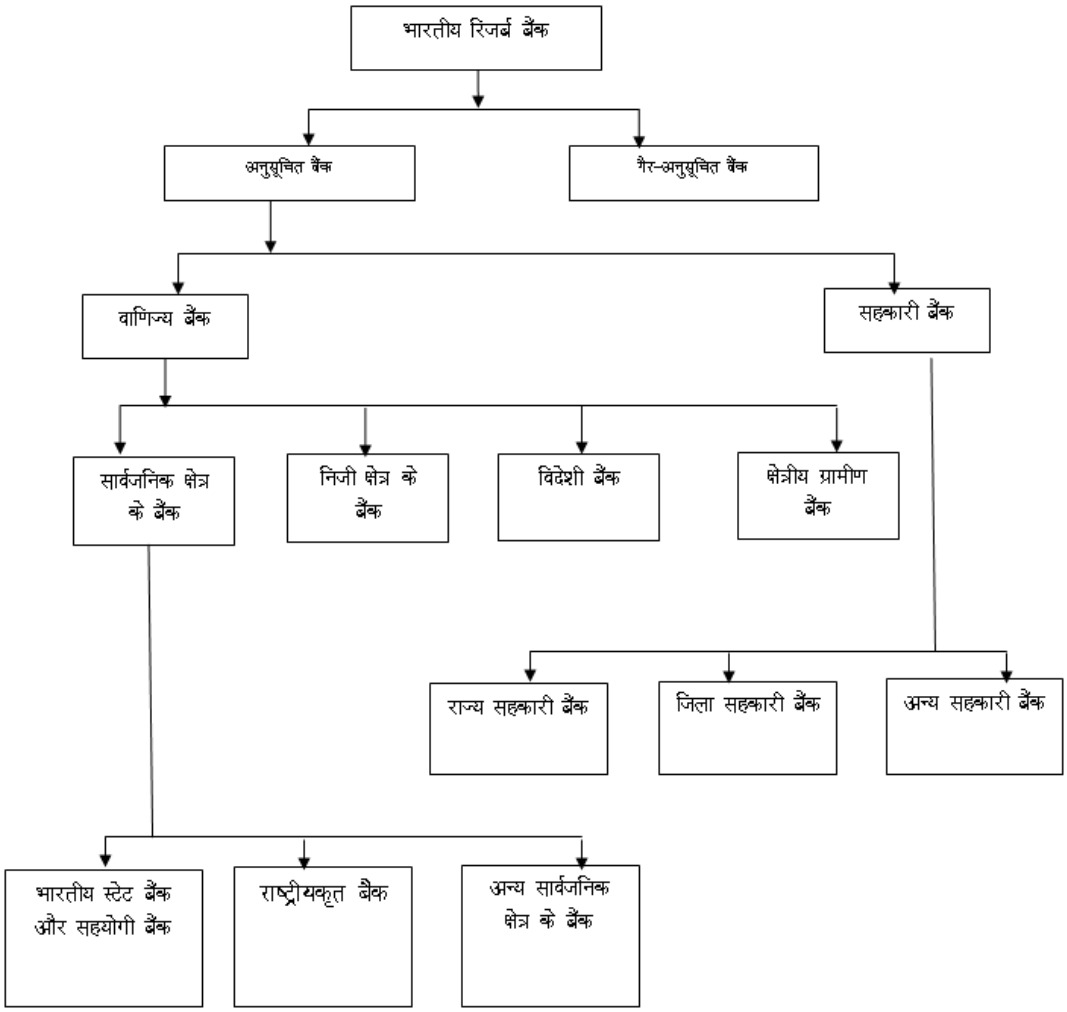


- **भारतीय रिजर्व बैंकः-** भारतीय बैंकिंग संरचना में सर्वोच्च शिखर पर भारतीय रिजर्व बैंक हैं, जिसे हम केन्द्रीय बैंक, बैकों का बैंक या सरकार का बैंक के नाम से भी जानते हैं। यह बैंक विश्व के प्रत्येक देशों में पाया जाता हैं क्योंकि सम्पूर्ण आर्थिक एवं वित्तीय प्रक्रिया का

संचालन इसी बैंक के माध्यम से होता हैं। इसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक, यूनाइटेड किंगडम में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड तथा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया आदि नामों से जाना जाता हैं।

भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना – **"भारतीय रिजर्व बैंक** अधिनियम १९३४ के तहत १ अप्रैल, १९३५ में की गयी थी।(२६) प्रारंभ में इसकी स्थापना एक निजी शेयर धारकों के द्वारा की गयी थी जिसमें – **"शेयर पूँजी को १०० पूर्ण रूप से भुगतान किये गये शेयरों में** बॉटा गया था।"(२७) अर्थात यह पूर्ण रूप से निजी स्तर पर कार्यरत थी इसीलिये – **"१५ अगस्त, १९४७ में** भारतीय स्वतंत्रता के बाद **१ जनवरी, १९४९** को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था"(२८) भारत सरकार को ऋण तथा वित्तीय मामलों में सलाह देना, बैंकों पर नियंत्रण रखना, बैंक दर के आधार पर अपने अधीन बैंकों को ऋण देना, नये नोटों का निर्गमन तथा पुराने नोटों का पुर्नःनिर्गमन करना तथा साख नियंत्रण करना आदि केन्द्रीय बैंक के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा यह देश की मौद्रिक नीति का गठन एवं कार्यान्वयन करना, समय-समय पर अपने अधीन बैंकों का निरीक्षण करना तथा विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुये मूल्य स्थिरता बनाये रखना आदि कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किये जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं जो कि केन्द्रीय निदेशक मंडल द्वारा संचालित एवं नियंत्रित हैं। यह केन्द्रीय निदेशक मंडल २१ सदस्यों से बना हुआ हैं जिसमें एक गवर्नर, ४ उप राज्यपाल, दो वित्त मंत्रालाय के प्रतिनिधि (मुख्य रूप से आर्थिक मामलों के सचिव और वित्तीय सेवा सचिव), दस सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चार निर्देशक, जो कि भारत के चार बड़े शहरों जैसेः- मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई तथा राजधानी नई-दिल्ली के स्थानीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में पदस्थ हैं, इत्यादि शामिल हैं। सम्पूर्ण भारत में रिजर्व बैंक के १९ क्षेत्रीय कार्यालय और ४ सब-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं।

वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर **श्री शक्तिकाँत दास हैं** जिन्होंने ४ सितम्बर, २०१६ में पदभार ग्रहण किया हैं।(२९)

- **अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकः-** भारतीय बैंकों को बैंकिंग संरचना की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया हैं बैंकों का गठन, कार्यप्रणाली, प्रबंधन एवं नियंत्रण के दृष्टिकोण से हम अनुसूचित बैंकों और गैर-अनुसूचित बैंकों के बीच अन्तर को इस प्रकार समझ सकते हैं।

**अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों के बीच अन्तर**

| क्र | आधार | अनुसूचित बैंक | गैर-अनुसूचित बैंक |
|---|---|---|---|
| १ | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ | अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ के तहत जारी सूची में शामिल हैं। | गैर-अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियमों को स्वीकार नहीं करते हैं और न ही यह सूची में शामिल हैं। |
| २ | पूँजी के आधार पर | अनुसूचित बैंकों की आरंभिक आरक्षित पूँजी ५ लाख होना चाहिये। | गैर-अनुसूचित बैंकों में पूँजी का कोई प्रबंधन नहीं हैं। |
| ३ | ऋण के आधार पर | अनुसूचित बैंके भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें यह ऋण एक निश्चित अवधि में अदा करना पड़ता हैं। | गैर-अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। |

**अनुसूचित बैंकः-** भारत की अधिकाँश बैंके अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल हैं। अनुसूचित बैंक की परिभाषा के अनुसार – **"ऐसे कोई भी बैंक** जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ के तहत दूसरी सूची में सूचीबद्ध हैं, अनुसूचित बैंक कही जाती हैं।(३०) इसके अन्तर्गत

सभी राष्ट्रीयकृत बैंके, वाणिज्य बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक तथा सहकारी बैंक आदि शामिल हैं। **भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार** – "देश में अनुसूचित बैंकों के कार्य करने के लिये कम से कम ५ लाख रूपये की आरक्षित पूँजी होनी चाहिये तभी यह कार्य कर सकती हैं।"(३०)

इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उक्त दोनों अवधियों के लिये ऋण प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त हैं।

अनुसूचित बैंकों को दो भागों में बॉटा गया हैं। पहला वाणिज्य बैंके और दूसरा सहकारी बैंके आदि। वाणिज्य बैंक वे बैंक होती हैं जिन्हें– "बैंकिंग विनिमय अधिनियम, १९४९ के तहत विनियमित किया गया हैं।"**(३१)** इन बैंकों का गठन पूर्णरूप से लाभ अर्जित करने के लिये किया गया हैं। इनका प्राथमिक कार्य जनता की जमा को स्वीकार करना और उन्हें आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान करना हैं।

वाणिज्य बैंकों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया हैं।

१. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

२. निजी क्षेत्र के बैंक

३. विदेशी बैंक

४. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकः**– भारत में बहुत बड़े स्तर पर जो बैंके कार्यकर रही हैं वह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंके हैं। इन बैंकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक हिस्सेदारी हैं। इसके अन्तर्गत ऐसे बैंक शामिल किये गये हैं जिनका सन १९६९ एवं १९८० में राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह बैंके – **"देश के कुल बैंकिंग व्यवसाय** का ७५ः से अधिक का हिस्सा रखते हैं।**(३१)** सार्वजनिक क्षेत्र की बैंके पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक और इसके ५ सहयोगी बैंक हैं। इस बैंक को कारोबार और लाभ के दृष्टिकोण से दुनिया के ५० शीर्ष बैंकों में शामिल किया गया हैं।

वर्तमान में कुल २१ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिसके नाम निम्नलिखित हैं।

**भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की सूची**

| क्रम | नाम | क्रम | नाम |
|---|---|---|---|
| १ | भारतीय स्टेट बैंक | १३ | बैंक ऑफ बड़ौदा |
| २ | बैंक ऑफ इंडिया | १४ | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| ३ | इलाहाबाद बैंक | १५ | यूनाइटेड बैंक |
| ४ | केनरा बैंक | १६ | विजया बैंक |
| ५ | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | १७ | देना बैंक |
| ६ | इंडियन ओवरसीज बैंक | १८ | इंडियन बैंक |
| ७ | आई.डी.बी.आई. बैंक | १९ | पंजाब एण्ड सिंध बैंक |
| ८ | ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स | २० | पंजाब नेशनल बैंक |
| ९ | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | २१ | सिंडिकेट बैंक |
| १० | कॉर्पोरेशन बैंक | | |
| ११ | आन्ध्रा बैंक | | |
| १२ | यूको बैंक | | |

**स्त्रोतः– Banking. (www.Paisabazaar.com)**

भारतीय केबिनेट ने – **"०२ जनवरी, २०१६** में विजया एवं देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी प्रदान की हैं जो कि १ अप्रैल, २०१६ से प्रभावी होगी। इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जायेगा तथा इस क्षेत्र के बैंकों की संख्या २१ से घटकर १६ रह जायेगी।"**(३२)**

**निजी क्षेत्र के बैकः-** भारत में निजी स्तर के बैंकों की नीव उस समय रखी गयी थी जब भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अन्तर्गत वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसी नीतियॉ अमल में लायी गयी थी हालॉकि कुछ निजी क्षेत्र के बैंक सन १९६९ में किये गये बैंके के राष्ट्रीयकरण के पूर्व भी संचालित थी लेकिन उनकी कार्य प्रक्रिया उतनी सक्रिय नहीं थी जितनी की आज हैं।

निजी क्षेत्र के बैंकों में उन बैंकों को शामिल किया गया हैं जिनकी हिस्सेदारी या इक्विटी पूर्ण रूप से निजी शेयर धारकों के पास हैं परन्तु वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये कानून या अधिनियमों के तहत कार्यरत हैं।

वर्तमान में भारत में कुल २१ बैंक निजी स्तर पर कार्यरत हैं जो कि निम्नलिखित हैं।

**भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों की सूची**

| क्रम | नाम | क्रम | नाम |
|---|---|---|---|
| १ | एच डी एफ सी बैंक | १३ | कैथोलिक सायरैन बैंक |
| २ | आई सी आई सी आई बैंक | १४ | फेडरल बैंक |
| ३ | एक्सिस बैकं (।गपे ठंदा) | १५ | जम्मू और कश्मीर बैंक |
| ४ | यस बैंक (ल्मे ठंदा) | १६ | कर्नाटका बैंक |
| ५ | इनडसडन्ड बैंक (प्दकनेपदक ठंदा) | १७ | धनलक्ष्मी बैंक |
| ६ | कोटक महिन्द्रा बैंक | १८ | दक्षिण भारतीय बैंक |
| ७ | डी सी बी बैंक | १९ | लक्ष्मी विलास बैंक |
| ८ | बंधन बैंक | २० | आर बी एल बैंक |
| ९ | आई डी एफ सी बैंक | २१ | कैरूर व्यास बैंक |
| १० | सिटि यूनियन बैंक | | |
| ११ | तमिलंड मर्केन्टाईल बैंक | | |
| १२ | नैनीताल बैंक | | |

**स्त्रोतः- Banking. (www.Paisabazaar.com)**

**विदेशी बैंकः-** विदेशी बैंक वह बैंक होते हैं जिनका मुख्य या कार्यालय विदेशों में होता हैं लेकिन वह भारत में एक शाखा कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। भारत में इन बैंकों की उपस्थिति को दो रूपों से स्पष्ट किया गया हैं। पहला – भारत में विदेशी बैंक एवं भौतिक शाखा के रूप में कार्य करना तथा दूसरा – भारत में प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से कार्य करना आदि। इसके अलावा कुछ विदेशी बैंकों ने भारत में नेटवर्किंग प्रक्रिया अर्थात इन्टरनेट द्वारा बैकिंग कार्य के माध्यम से प्रवेश किया हैं। **जी.के. टुडे डॉट इन के अनुसारः-** भारत में विदेशी बैंक देश के कुल शाखा नेटवर्क का १: से भी कम खाते हैं हालॉकि उनके पास कुछ बैंकिंग क्षेत्र की सम्पत्ति का लगभग ७: हिस्सा हैं।"**(३३)**

भारत में जितनी भी विदेशी बैंकों की शाखाऐं हैं उनका स्तर बहुत ही उच्च हैं। उन्होंने उन क्षेत्रों में अपना बैंकिंग कार्य किया हैं जहॉ पर धन राशि अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सके। ये बैंके विशेष रूप से व्यापार वित्त, थोक, उधार, निवेश बैंकिंग और ट्रेजरी जैसी सेवाओं में संलग्न हैं।

भारत में विदेशी बैंकों की स्थापना के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक की स्पष्ट नीति हैं। केन्द्रीय बैंक में केवल उन देशों को हमारे देश में शाखाओं को खोलने की अनुमति प्रदान की हैं जिन देशों में भारतीय बैंकों की शाखा खोलने हेतु किसी प्रकार के कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाये हैं अर्थात भारत सरकार ने **ळपअम ंदक जंम** के सिद्धॉत पर विदेशी बैंकिंग प्रक्रिया पर कार्य किया हैं।

भारत में विदेशी बैंकों की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रकार कुछ दिशानिर्देश जारी किये हैं।

- विदेशी बैंकों की शाखाओं को न्यूनतम पूँजी आवश्यकता को पूरा करना होगा अर्थात ५ बिलियन डॉलर।
- बैंकों को बेसल मानक (बैंकिंग आरक्षित पूँजी) के अनुसार अनिवार्य पूँजीगत आवश्यकता को पालन करना होगा।
- उन्हें १०: पर न्यूनतम सी आर ए आर बनाये रखने की आवश्यकता हैं।
- भारत में विदेशी बैंकों के लिये प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य ४०: हैं।

भारत में विदेशी बैंके **"नवम्बर, २०१८ के अनुसार** ४५ हैं जो कि अपनी २८६ शाखाओं के साथ सम्पूर्ण भारत में कार्यरत हैं।"**(३३)** सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टड बैंक तथा एच एस बी सी भारत के कुछ विदेशी बैंक हैं।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकः-** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रायोजित भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर की गयी हैं। जिसका उददेश्य ग्रामीण वित्तीय समावेशन हेतु गॉव के भूमिहीन, कृषक मजदूरों, सीमाँत किसानों एवं गॉव के कमजोर वर्ग के लोगों जैसेः- अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधा मुहैया कराना हैं। जिससे कृषि विकास के साथ-साथ इसमें संलग्न लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास किया जा सके।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का गठन तीन निकायों जैसेः- **"प्रायोजित बैंक, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार,** इसमें केन्द्र सरकार का ५०:ए प्रायोजित बैंक का ३५:ए और राज्य सरकार का १५: का हिस्सा शामिल हैं, के द्वारा किया गया हैं।"**(३०)** भारत के कई वाणिज्य बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किये हैं। जिनमें महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक तथा हिमाचल ग्रामीणी बैंक शामिल हैं।

यदि हम इन बैंकों के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य पर दृष्टि डालें तो यह कहा जाता हैं कि इनकी स्थापना - **"२६ सितम्बर, १९७५ में पारित एक अंध्यादेश के प्रावधानों के तहत की गयी थी** यह अंध्यादेश था आर आर बी (त्त्ठ) अधिनियम १९७६ कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराना जिसके परिणामस्वरूप गॉधी जयंती अर्थात २ अक्टूबर, १९७५ को ५ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये थे। बाद में इंदिरा गॉधी के शासन काल के दौरान नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी थी।**(३४)**

वर्तमान में - **"५६ क्षेत्रीय** ग्रामीण बैंक भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक हैं जिसने लगभग ४४ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया हैं।"**(३५)**

नवीनतम जानकारी के अनुसार - **"५ जनवरी, २०१९ को** तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे- पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक एवं सतलज ग्रामीण बैंक उक्त तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया हैं जिनका प्रायोजित बैंक पंजाब नेशनल बैंक हैं। इस विलय के बाद भारत में इन बैंकों की संख्या ५६ से घटकर ५३ रह गयी हैं।**(३२)**

**भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया हैं।**

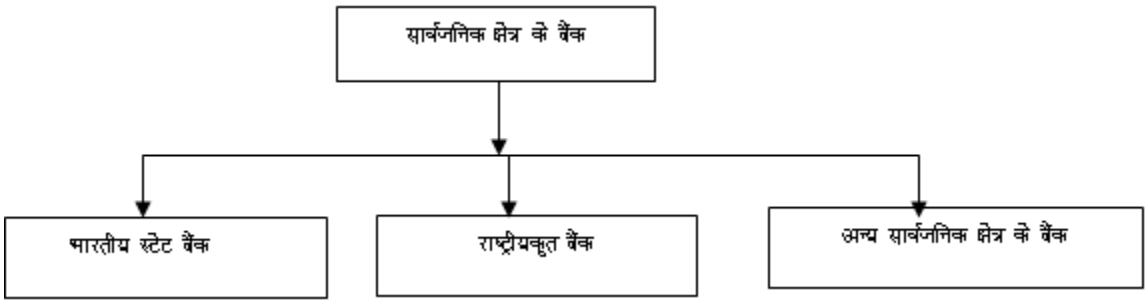

**भारतीय स्टेट बैंकः-** भारत का सबसे बड़ा एवं पुराना बैंक लाभ तथा कारोबार की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक हैं जिसका गठन इम्पीरियल बैंक की स्थापना के पश्चात हुआ था (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में दी गयी हैं।) यह एक सरकारी वैधानिक निकाय हैं जिसका मुख्यालय मुम्बई, महाराष्ट्र में हैं।

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक अपने विकास की दृष्टि से इतना अधिक आगे बढ़ चुका हैं कि इसे - **"वर्ष २०१८ में विश्व के सबसे बड़े निगमों की फॉरचून** ग्लोबल ५०० की सूची में भारतीय स्टेट बैंक को २१६ वे स्थान पर रखा गया हैं। यह भारत की सम्पत्ति में २३ः बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा बैंक बन गया हैं इसके अलावा कुल ऋण एवं जमा बाजार का एक चौथाई हिस्सा रखता हैं।"**(३६,३७)**

भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों की जमा एवं ऋण संबंधी सुविधाऐं प्रदान करने के अलावा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता हैं। जिसमें जीवन बीमा, क्रेडिट कार्ड, मयुचूअल फण्ड, पेंशन फण्ड और मुद्रा बाजार में प्राथमिक डीलरशिप आदि शामिल हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह बैंक चार क्षेत्रों जैसेः- ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग इत्यादि कार्यों में संलग्न हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की सम्पूर्ण भारत में - **"२४००० शाखाऐं, ५६,००० एटीएम और विश्व के ३६ देशों में लगभग १६५ बैंकिंग कार्यालय स्थित हैं।"(३८)**

भारतीय स्टेट बैंक की **वार्षिक रिपोर्ट (२०१८-१६) के अनुसार** - "भारतीय स्टेट बैंक की कुल पूँजी ३६८०६१४ करोड़ रू. तथा कर्मचारियों की संख्या २५७२५२ हैं।"**(३६)**

**राष्ट्रीयकृत बैंकेः-** राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में उन बैंकों को शामिल किया गया हैं। जिनका १६६६ एवं १६८० में राष्ट्रीयकरण किया गया था (बैंकों की सूची ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में दी गयी हैं।)

**अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकेः-** इसके अन्तर्गत शामिल समस्त बैंकों की सूची का विवरण पूर्व में ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में दिया गया हैं।

**सहकारी बैंकेः-** सहकारी बैंकों की स्थापना सहयोग या सहकारिता के आधार पर की गयी हैं जिसका उददेश्य शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाऐं उपलब्ध कराना हैं। भारत में सहकारी बैंकों की स्थापना सन १६०४ में पारित सहकारी समितियॉ अधिनियम के साथ प्रारंभ हुयी थी। इस अधिनियम के तहत यह उन लोगों जैसे शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों, स्व-रोजगार हेतु, घर खरीदने तथा शैक्षिक ऋण जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों, पशुपालन, डेयरी, हैचरियों, लघु व कुटीर उद्योगों में संलग्न लोगों को वित्तीय सुविधाऐं मुहैया कराना हैं। इसके बाद अन्य सहकारी बैंकों की स्थापना सन १६१२ में पारित सहकारी समितियॉ अधिनियम के तहत की गयी थी। ये बैंकें विशेष रूप से **नो प्रोफिट नौ लोस के** आधार पर कार्य करती हैं।

**भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तर पर किया गया हैं।**

प्रथमः- राज्य सहकारी बैंक

द्वितीयः- जिला सहकारी बैंक

तृतीयः- अन्य सहकारी बैंक अर्थात प्राथमिक साख सहकारी समितियॉ

**प्रथमः-** राज्य सहकारी बैंक, सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था होती हैं जो भारत के प्रत्येक राज्य में स्थापित की गयी हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लायसेंस प्राप्त हैं। राज्य सहकारी बैंके एक प्रकार से जिला सहकारी बैंकों पर नियंत्रण और साख संबंधी कार्यो को पूर्ण करने का काम करती हैं।

**द्वितीयः-** जिला स्तर पर कार्यरत सहकारी बैंकों का कार्य शहरी क्षेत्र के छोटे-व्यवसायियों तथा स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु वित्त उपलब्ध कराती हैं। ये बैंकके ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक साख सहकारी समितियों को भी वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं।

**तृतीयः-** अन्य सहकारी बैंकों के अन्तर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण स्तर पर संचालित प्राथमिक साख सहकारी समितियों को शामिल किया गया हैं। इन समितियों में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो स्थानीय स्तर पर निवासरत हैं और जो अपनी वित्त संबंधी जरूरतों को पूर्ण करना चाहते हो, ये बैंके अपनी साख संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों से समय-समय पर ऋण प्राप्त करती हैं।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिये भारत सरकार हमेशा तत्पर रहा हैं इसलिये ग्रामीण स्तर पर वित्तीय समावेशन हेतु बैंकों को, विशेषकर सहकारी बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं और इसी का परिणाम हैं कि आज सहकारी बैंकों का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर पहुँच गया हैं। **वर्ष २०१७ के अनुसार - "भारत में** सहकारी बैंकों में संलग्न सदस्यों की संख्या लगभग २०० मिलियन तक पहुँच गयी हैं। इसमें ग्रामीण स्तर के सदस्यों का प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात ६७ हैं जो कि कुल ग्रामीण ऋण का लगभग ४६: हिस्सा ऋण के रूप में प्राप्त करते हैं।"(४०)

नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल ५३ सहकारी बैंके कार्यरत हैं जो कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों विशेष रूप से सीमांत किसानों, छोटे उद्यमियों तथा स्व-रोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने के लिये सक्रिय रूप से वित्तीय सुविधाऐं उपलब्ध कराने में संलग्न हैं।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना में दो और बैंक शामिल हैं जो कि निम्नलिखित हैं।

१. **छोटे वित्तीय बैंक (उंसस थ्पदंदबम ठंदो)**

२. **भुगतान बैंक (च्ंलउमदज ठंदो)**

सर्वप्रथम हम इन दोनों बैंकों के बीच अन्तर को समझने का प्रयास करेंगे।

**भुगतान बैंक और छोटे वित्तीय बैंकों के बीच अन्तर**

| क्रम | भुगतान बैंक | छोटे वित्तीय बैंक |
|---|---|---|
| १ | भुगतान बैंक में प्रति खाता जमा राशि पर १ लाख की सीमा हैं। | छोटे वित्तीय बैंकों की कोई सीमा नहीं हैं। |
| २ | भुगतान बैंक उधार नहीं दे सकते हैं। | छोटे वित्तीय बैंक ऋण दे सकते हैं। |
| ३ | भुगतान बैंकों को कुछ मापदण्ड के तहत साख देने का अधिकार प्राप्त हैं। | छोटे वित्तीय बैंक के लिये भारतीय रिजर्व बैंक चाहता हैं कि बैंक अपनी कुल जमा का ७५: ऋण प्रदान करें। |

**स्त्रोतः- (www.livemint.com), 17 Sep. 2015**

**1- छोटे वित्तीय बैंकः-** भारत में छोटे बैंकों का गठन मूलरूप से उन लोगों के लिये किया गया हैं जो वित्तीय सुविधाओं से वंचित हैं या अन्य वाणिज्य एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन लोगों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सुविधा मुहैया नही करायी हैं। इसमें भूमिहीन व छोटे किसान, असंगठित कामगार, सीमांत किसान व लघु व कुटीर उद्योगों में संलग्न लोगों को शामिल किया गया हैं।

**भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसारः-** "भारत में स्थित ऐसे छोटे वित्तीय बैंक जिन्हें आर.बी.आई. से लायसेंस प्राप्त हैं, जमा एवं उधार संबंधी बैंकिंग सुविधाऐं प्रदान कर सकते हैं। इसका उददेश्य वित्तीयविहीन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन प्रदान करना हैं।"(४१)

छोटे वित्तीय बैंकों की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियम व अधिनियम पारित किये हैं जो कि निम्नलिखित हैं।

- ये बैंक सार्वजनिक कंपनी अधिनियम, १९५६ के तहत स्थापित किये गये हैं।

- ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- ये बैंक किसी भी क्षेत्र के लिये प्रतिबंधित नहीं होगें।
- ये बैंक ग्रामीण एवं अर्द्व शहरी क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देना, आर्थिक गतिविधियों हेतु ऋण देना इत्यादि दोनों उददेश्यों से कार्य करेंगे।
- इसके पोर्टफोलियों में ५०: ऋण २५ लाख की श्रेणी में होना चाहिए।"(४२)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन अधिनियमों के आधार पर १६ सितम्बर, २०१५ को भारत सरकार ने १० संस्थाओं को छोटे वित्त बैंक स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की हैं जो कि निम्नलिखित हैं।

**भारत में स्थापित छोटे वित्तीय बैकों की सूची**

| S.No. | Name of Banks |
|---|---|
| 1 | Au Small Finance Bank Ltd. |
| 2 | Capital Small Finance Bank Ltd. |
| 3 | Finance Small Finance Bank Ltd. |
| 4 | Equitas Small Finance Bank Ltd. |
| 5 | ESAF Small Finance Bank Ltd. |
| 6 | Suryoday Small Finance Bank Ltd. |
| 7 | Ujjivan Small Finance Bank Ltd. |
| 8 | Utkarsh Small Finance Bank Ltd. |
| 9 | North East Small Finance Bank Ltd. |
| 10 | Jana Small Finance Bank Ltd. |

**स्त्रोतः- Banking (www.paisabazaar.com).**

**2- भुगतान बैंकः-** वह भारतीय बैकिंग संरचना के क्षेत्र में एक नया मॉडल हैं जिसे आर. बी. आई. (ठप) द्वारा परिकल्पित किया गया हैं। भुगतान बैंक पूर्व बैकिंग सेवाओं की मदद करने एवं वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु स्थापित किये गये हैं।

**भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसारः-** भुगतान बैंक वे बैंक हैं जो प्रतिबंधित जमा को स्वीकार करते हैं जो वर्तमान में प्रति ग्राहक १००००० तक सीमित हैं तथा इसे बढ़ाया भी जा सकता हैं।"(४३) ये बैंक चालू खाता तथा बचत खाता दोनों संचालित कर सकते हैं लेकिन ऋण एवं क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। भुगतान बैंक एटीएम (।ज्ड), नेट बैंकिंग और मोबाईल बैकिंग जैसी सेवाऐं प्रदान करेंगे।

भुगतान बैकों की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने - **"२३ सितम्बर, २०१३ में नचिकेत मोर की** अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।(४४) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट ७ जनवरी, २०१४ में पेश की थी - "जिसमें बैंक की एक नयी श्रेणी के गठन की सिफारिश की जिसे भुगतान बैंक कहा जाता हैं।(४५) समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई (ठप) ने - **"१७ जुलाई, २०१४** में भुगतान बैकों के लिये दिशा निर्देश जारी किये(४६) तथा **२७ नवम्बर, २०१४** को ठप ने अंतिम दिशा निर्देश जारी कर बैकों की स्थापना के आदेश पारित किये थे।(४७) तब से यह बैंक भारत में कार्यरत हैं और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही हैं।

भुगतान बैंकों की सूची में निम्नलिखित बैंक शामिल हैं।

**वर्ष २०१५ के अनुसार भारत में भुगतान बैकों की सूची।**

| क्रम | बैंक का नाम |
|---|---|

| | |
|---|---|
| १ | आदित्य बिड़ला नुवों लि. |
| २ | एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज लि. |
| ३ | चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन लि. |
| ४ | रिलायंस उद्योग लिमिटेड |
| ५ | टैक महिन्द्रा लिमिटेड |
| ६ | वोडाफोन एम-पैसा लिमिटेड |
| ७ | फिनो पे-टैक लिमिटेड |
| ८ | डाक-विभाग |
| ९ | राष्ट्रीय सिक्योरिटीज |

**स्त्रोतः- ्रूणसपअमउपदजण्बवउद्धए १६ैमचजमउइमत २०१५ण**

**भारत में बैंकों की स्थितिः-** भारत में बैकिंग व्यवसाय वित्तीय दृष्टिकोण से सबसे मजबूत तथा प्रभावशाली रहा हैं। जिस प्रकार भारत की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुये बैकिंग प्रणाली ने कई महत्वपूर्ण आयाम हासिल किये हैं। जैसेः- नियमित वित्तीय प्रवाह, पर्याप्त मात्रा में साख का सृजन एवं ऋण की उपलब्धता और पूॅजी निर्माण की प्रक्रिया, जो कि निवेश करने के लिये अति-महत्वपूर्ण हैं, में सतत रूप से वृद्धि करने में सक्षम हुयी हैं। यही कारण हैं कि आज भारतीय बैकिंग पद्धति को विश्व में सबसे मजबूत एवं सबसे बड़ी पद्धति के रूप में जाना जाता हैं।

भारत में बैकों ने लोगों को न केवल बचत करने हेतु प्रोत्साहित किया हैं बल्कि पूॅजी निवेश हेतु पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने में भी समक्ष हुयी हैं जो कि औद्योगिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसी भी देश का औद्योगिक विकास उस देश की पूॅजी निर्माण क्षमता पर निर्भर करता हैं और वह तभी संभव हैं जब उस देश में बचत की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो, बैकों ने ऐसे क्षेत्रों में बचत की मात्रा को प्रोत्साहित करने का कार्य किया हैं जो कई वर्षो तक वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से अपनी निम्न अवस्था में चलायमान रहे थे।

११ जुलाई, १९६९ में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया। १४ बैकों का राष्ट्रीयकरण वित्तीय प्रवाह के दृष्टिकोण से सफल सिद्ध हुआ। इस अवधि में भारतीय बैकों ने और तेज गति पकड़ी तथा बैकों की स्थापना, जो कि पूर्व में केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित थी, ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से दूर-दराज स्थित गॉवों में स्थापना की गयी थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग वित्तीय सुविधाओं से वंचित न रह सके और ग्रामीण स्तर पर संचालित लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल सके क्योंकि आज भी भारत की अधिकॉश जनता इस प्रकार के उद्यमों में कार्यरत होकर अपना जीवन यापन कर रही हैं।

भारतीय बैकिंग उद्योग ने अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा संचालित छोटे वित्त बैंक एवं भुगतान बैंक जैसे नये मॉडलों को देखा व अपनाया हैं जिससे भारत के बैकिंग व्यवसाय में और विकास हुआ हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली, जो कि पूर्ण रूप से नगदहीन इलैक्ट्रोनिक्स पद्धति पर आधारित हैं, सक्रिय व प्रभावकारी रही हैं। ऐसा माना जाता हैं कि **''भारत की डिजिटल प्रणाली विश्व के २५ देशों में सबसे अधिक विकसित और सक्रिय प्रणाली हैं जिसमे ंभारत तत्काल भुगतान सेवा की प्रक्रिया में ५वें स्तर पर पहुॅच गयी हैं।(४८)**

वित्तीय बाजार के दृष्टिकोण से बैकिंग प्रणाली में विस्तार हुआ हैं। जिसके अन्तर्गत - **''२७ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक,** २१ निजी क्षेत्र, ४६ विदेश बैकं, ५६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, १५६२ शहरी सहकारी बैंक तथा ६४३८४ ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं।**''(४८)**

भारतीय बैंक ऋण प्रदान करने के मामलें में भी अग्रणी रही हैं। इन बैकों ने - **''दिसम्बर, २०१४ में १८१ बिलियन** का ऋण दिया था जो कि दिसम्बर, २०१७ तक बढ़कर २८१ बिलियन तक पहुॅच गया हैं।**(४८)** ऋण के मामले में भारतीय बैकिंग व्यवसाय वित्तीय बाजार में चौथा सबसे बड़ा बाजार के रूप में उभरकर आया हैं। यह लोगों के साथ-साथ निवेश विकास हेतु उद्यमियों को भी ऋण देने का कार्य करता हैं। नवीनतम वर्ष अर्थात - **''२०१६ में भारत की १०ः वाणिज्यिक बैकों ने** कुल ६३,७५१.१७ बिलियन तक ऋण की मात्रा को बढ़ाया हैं तथा कुल जमा राशि भी बढ़कर १,२०,८१८.६२ बिलियन डॉलर हो गयी हैं।**(४९)**

भारतीय रिजर्ब बैंक की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा बैकिंग क्षेत्र में अपनाये गये दो मॉडल जैसे- छोटे वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक, वित्तीय समावेशन की दृष्टि से अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। अब तक इन बैकों द्वारा ६५० शाखाऐं खाली जा चुकी हैं। इस दृष्टि से- **''वर्ष २०१८ में इस क्षेत्र के बैकों की कुल इक्विटी फंडिंग** ३६.८८ बिलियन डॉलर से बढ़कर ६६.३१ बिलियन डॉलर तक पहुॅच गयी हैं।**(४८)** जो कि भारत सरकार द्वारा की गयी पहल का एक उत्तम नमूना कही जा सकती हैं।

भारत के बैकिंग क्षेत्र को आगे बढ़ाने में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का योगदान भी सराहनीय रहा हैं। उन्होंने देश के सर्वाधिक लोगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष २०१४ में जन-धन खाता नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया - **''जन-धन खाता योजना १४ अगस्त, २०१४ को** मंजूर तथा २८ अगस्त, २०१४ को लागू हुयी थी तथा वर्ष २०१८ तक इस योजना के अन्तर्गत ३२.४१ करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं।**(५०)** प्रारंभ में इस योजना के तहत ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जिनकी उम्र ६० वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब ६५ वर्ष कर दिया गया हैं। जन-धन खाता योजना में दिन-प्रतिदिन बढ़ती ग्राहकों की संख्या के कारण - **''२६ मई, २०१६** में कुल जमा राशि बढ़कर ६८३.२० बिलियन यू.एस.ए डॉलर तथा ३५५.४ मिलियन खाते खोले जा चुके हैं।**''(४६)** अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने यह घोषण की हैं कि - **''इस योजना के तहत जुड़े** खाता धारकों के लिये ओवर ड्राफ्ट की सुविधा को बढ़ाकर दोगुना अर्थात १० हजार रूपये कर दिया गया हैं।**''(५०)** जो कि पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत ओवर ड्राफ्ट की सुविधा के तहत केवल ५ हजार रूपये तक की राशि शामिल थी।

जन धन खाता योजना के संबंध में भारत सरकार ने यह घोषणा की हैं कि खाता धारकों को २ लाख रूपये का दुर्घटना बीमा भी दिया जायेगा।

वर्ष २०१८ में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भारत के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को तत्काल वित्तीय सुविधा प्रदान करने हेतु - **''चैठसवंदॅपदह ६ डपदनजमेण्बवउ नामक वेबसाईट लॉच की हैं।**''(५१) यह वेबसाईट सबसे बड़े ऑनलाईन ऋण देने वाले मंच के रूप में उभरकर आयी हैं। यह एक ऐसी वेबसाईट हैं जो उद्यमियों को मात्र ५६ मिनट में या एक घण्टे से भी कम समय में १ करोड़ रू. तक का ऋण प्रदान कर सकती हैं।

भारत की आर्थिक विकास दर तथा आर्थिक वृद्धि दर में तेजी लाने के लिये **श्री नरेन्द्र मोदी जी ने** ८ अप्रैल २०१५ में एक मुद्रा योजना लॉच की थी।**(५२)** यहॉ मुद्रा का मतलब हैं माइक्रोयूनिटस डेवलपमेन्ट एवं रिफायनैसिंग ऐजेन्सी, जिसका उददेश्य लघु व सूक्ष्म स्तर पर उद्योगों को ऋण की सुविधाऐं प्रदान करना हैं। इस संबंध में मोदी जी यह मानते हैं कि सूक्ष्म व लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं क्योंकि देश की अधिकॉश जनता इस प्रकार के उद्यमों से अपनी जीवन यापन कर रही हैं इसलिये यदि हम इन उद्यमों पर ध्यान देते हैं तो देश की आर्थिक विकास एवं वृद्धि दर उक्त दोनों में विस्तार होना संभव हैं। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था शीर्ष पर पहुॅच सके। मुद्रा योजना के तहत - **''२३ मार्च, २०१८ तक** २२८१४४ करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किये जा चुके हैं जिसमें २२०५६६ करोड़ रूपये के ऋण बॉटे जा चुके हैं।**(५३)**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के विकास हेतु अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया हैं और इन बैकों की निम्न वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये - **''१२ बैकों को ४८२३६ करोड़ रूपये की धनराशि वितरित करने की घोषणा की हैं।(५४)** जिससे ये बैंक अपनी पूॅजी संबंधी जरूरतों को पूर्ण कर सके।

**भारत सरकार द्वारा १२ सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को प्रदान की गयी धनराशि**

| क्र | बैंक का नाम | धनराशि (करोड़ों में) |
|---|---|---|
| १ | कॉर्पोरेशन बैंक | ६०८६ करोड़ रू. |
| २ | इलाहाबाद बैंक | ६८९६ करोड़ रू. |
| ३ | बैंक ऑफ इंडिया | ४६३८ करोड़ रू. |
| ४ | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | २०५ करोड़ रू. |

| | | |
|---|---|---|
| ५ | पंजाब नेशनल बैंक | ५९०८ करोड़ रू. |
| ६ | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | ४११२ करोड़ रू. |
| ७ | आन्ध्रा बैंक | ३२५६ करोड़ रू. |
| ८ | सिंडिकेंट बैंक | १६०३ करोड़ रू. |
| ९ | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | ३१३३.७५ करोड़ रू. |
| १० | यूनाइटेड बैंक | ३१३३ करोड़ रू. |
| ११ | यूको बैंक | ३१३३ करोड़ रू. |
| १२ | इंडियन ओवरसीज बैंक | ३१३३ करोड़ रू. |

**स्त्रोतः- (www.livehindustan.com) 20 Feb. 2019**

इस प्रकार यह कहा जा सकता हैं कि भारतीय बैंकिग पद्धति का विकास एवं विस्तार करने में भारत सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं।

यद्यपि भारतीय बैंकिंग व्यवसाय ने वित्तीय समावेशन की दृष्टि से अर्थव्यवस्था का विकास एवं वृद्धि करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया हैं लेकिन फिर भी बैकिंग व्यवसाय आलोचनाओं की दृष्टि से अछूता नहीं रहा हैं। ऋण पूँजी, परिसम्पत्तियॉ और कार्यप्रणाली आदि सभी क्षेत्रों में बैकों की स्थिति दयनीय रही हैं। बैंक धोखाधड़ी तथा वित्तीय संकट भारतीय बैकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग रहा हैं। इस संबंध में **सन, १९१३ में जॉन मेनाई केन्स ने** भारत की बैकिंग पद्धति का सर्वेक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि – **"भारत में बैकिंग व्यवसाय** सर्वाधिक खतरनाक हैं इसलिये देश में बैकिंग पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिये सुरक्षित संभव सिद्धॉतों के आधार पर संचालित किया जाना चाहिये(५५) ताकि बैकिंग प्रणाली उचित रूप से चलायमान रह सके।

"वर्ष २०१५ से २०१८ तक भारत के २१ सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों ने लगभग ८७ः खराब ऋण प्रदान किये थे जबकि बैकिंग परिसम्पत्तियों में उनकी हिस्सेदारी ८७ः से कम हैं।"(५६) अर्थात बैकिंग पूँजी की तुलना में खराब ऋण देना एक प्रकार से बैंकों की दयनीय स्थिति को सूचित करता हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंक तो ऐसे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से पूँजी एकत्रित करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं हालॉकि इस क्षेत्र के बैकों के लिये – **"वर्ष २०१८ में** वित्त मंत्री ने ७९४० करोड़ रूपये के आवंटन की घोषण की हैं(५७) परन्तु फिर भी ये बैंक नगद धनराशि के मामले में निजी बैकों की तुलना में पिछड़े हुये हैं जबकि निजी बैंक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से अपनी नगद धनराशि की मात्रा में सतत रूप से वृद्धि कर रहे हैं लेकिन बैंकिंग कानून एवं अधिनियम के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस पद्धति से धनराशि एकत्रित करने में असमर्थ हैं।

यदि हम घाटे के दृष्टिकोण से भारतीय बैंकों का मूल्यॉकन करें तो यह पता चलता हैं कि – **"दिसम्बर, २०१५ से २०१८** तक इंडियन ओवरसीज बैंक, सैन्ट्रल बैंक तथा यूको बैंक उक्त दोनों ने हर तिमाही में नुकसान दर्ज किया हैं। इन बैकों का घाटा क्रमशः १२९९७, १०८०० तथा १०११३ करोड़ रूपये रहा हैं।"(५६) इसके अलावा इस अवधि में – **"आई.डी.वी.आई. बैंक ने** सबसे अधिक घाटा अर्थात २००२२ करोड़ रूपये दर्ज किया हैं। इसके बाद पॅजाब नेशनल बैंक १९७७४ करोड़ रूपये, भारतीय स्टेट बैंक १५०१० करोड़ तथा बैंक ऑफ इंडिया का १३१९० करोड़ रूपये रहा हैं।"(५६) पिछली ११ तिमाहियों में सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग ८ बैकों ने समूह के रूप में अपनी खराब सम्पत्ति की देखभाल के लिये उच्च प्रावधानों के कारण शुद्ध घाटा दर्ज किया हैं।

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में से केवल ६ बैकों ने **सितम्बर, २०१५ से २०१८ के** बीच डिपॉजिट पोर्टफोलियों को सीमित किया हैं। ये बैंक निम्न हैं जैसे- यूकों बैंक १६ः कॉर्पोरेशन बैंक १०ः इंडियन ओवरसीज बैंक ७ः बैंक ऑफ बड़ोंदा ३ः तथा देना बैंक १ः आदि(५६) इससे यह पता चलता हैं कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों की स्थिति कितनी दयनीय हैं क्योंकि डिपॉजिट पोर्टफोलियों की मात्रा ही एक बैंक को मजबूत वित्तीय स्थिति प्रदान करती हैं जिससे बैंके अपनी ऋण संबंधी जरूरतों को पूर्ण कर सके किन्तु बैकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये लगता हैं कि यह संभव नहीं हैं। यही कारण हैं कि अधिकॉश बैकें सरकारी फंडिंग को मोहताज बनकर रह जाती हैं और

भारत सरकार से धनराशि की उम्मीद करने लगती हैं जबकि भारत सरकार कभी-कभी ही अपने वार्षिक बजट में बैकों के लिये विशेष धनराशि के वितरण की घोषणा करती हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय बैकों की वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करना संभव नहीं हैं।

हालॉकि भारत में बैकों की स्थिति निम्न व पिछड़ी हुयी हैं लेकिन फिर भी इन बैकों ने वित्तीय समावेशन की दृष्टि से शहर से लेकर गॉवों तक अपनी अहम भूमिका अदा की हैं। आज देश जो विश्व स्तर पर शीर्ष स्थिति में पहॅुच पाया हैं, वह बैकों के कारण ही संभव हो पाया हैं। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास से लेकर औद्योगिक विकास तक बैकों की भूमिका अहम रही हैं।

**निष्कर्षः-** किसी भी देश में जब वित्तीय समावेशन की बात आती हैं तो केवल एक ही संस्था का नाम आता हैं और वह हैं बैंक, ये वे संस्थाऐं होती हैं जो लोगो की जमापूॅजी को स्वीकार करके उन्हें आवश्यकतानुसार समय-समय पर ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं। बैंक जमा पूॅजी के आधार पर अपनी साख की मात्रा में सतत रूप से वृद्धि करने में सक्षम होती हैं तथा यही साख की मात्रा आम जनता से लेकर छोटे व बड़े उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में मदद करती हैं। भारत में भी बैकों की कार्यप्रणाली इसी प्रकार भी हैं। हमारे देश में बैकों की संरचना के अन्तर्गत कई बैकें शामिल हैं जैसे- वाणिज्य बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और विदेशी, छोटे एवं भुगतान बैंक आदि। उक्त सभी बैकों की कार्य प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हैं। जहॉ एक तरफ सार्वजनिक एवं वाणिज्य बैकें आम जनता की जमा को स्वीकार करके ऋण देने का काम करती हैं वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैकों ने ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के सीमॉत, गरीब व लघु उद्यमियों को वित्त प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं।

भारत के दूर-दराज गॉवों में स्थित लोग कई वर्षों से वित्तीय सुविधाओं से वंचित थे, जिसे पूर्ण करने में या वित्तीय सुविधाऐं उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा उनकी सहयोगी बैकों (भूमि विकास बैक, बंधक बैंक, छोटे बैंक) ने ऋण प्रदान करके न केवल इन लोगों को वित्तीय दृष्टि से देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास करने में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया हैं। जहॉ एक ओर बैकें देश के नागरिकों की वित्त संबंधी जरूरतों को पूर्ण करती हैं वही दूसरी ओर लघु-मध्यम व कुटीर उद्योगों को अपनी जमा पूॅजी के आधार पर निवेश हेतु ऋण उपलब्ध कराके देश के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग देती हैं। बैकों ने देश के संरचनात्म ढॉचे, यातायात व परिवहन तथा औद्योगिक ढॉचें में वित्तीय दृष्टि से विकास करके देश के अधिकॉश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया हैं। लेकिन इन सब संभावनाओं के बावजूद भारतीय बैंकिंग व्यवसाय अपनी जीर्णशीर्ण अवस्था में कार्य कर रहा हैं। कारण पूॅजी का अभाव तथा बैकों द्वारा प्रदान किया गया खराब ऋण, बैंक धोखाधड़ी व वित्तीय संकट भारतीय बैंकों का अभिन्न अंग रहा हैं। जिससे बैंके दिन-प्रतिदिन दयनीय अवस्था में प्रवेश करती जा रही हैं। भारत की अधिकॉश बैकें विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक कई दिनों से घाटे में चल रहा हैं जिसके लिये बैंक द्वारा प्रदान किये गये खराब ऋण जिम्मेदार हैं। अतः यदि हमें अपने देश की बैंकिंग संरचना में सुधार करना हैं तो बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये नियम, कानून व अधिनियमों को सख्ती से अपनाना होगा, ऋण देते समय सावधानियॉ रखनी होगी ताकि बुरे या खराब ऋणों से बचा जा सके क्योंकि यही ऋण बाद में बैकों की वित्तीय स्थिति को दयनीय अवस्था में पहॅुचा देते हैं, तभी भारतीय बैंकिंग व्यवसाय में सुधार संभव हो सकेगा।

दक्षिण भारत में हिन्दी की स्वीकार्यता और समर्थन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। यह कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि बदली हुई परिस्थितियों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाएं आपसी सामंजस्य से विकास और रोजगार के नये अवसर दे सकते हैं। हिन्दी विरोध की राजनीति से आम आदमी को क्या लाभ है? क्या यह व्यापक सामाजिक ताने-बाने को चोट नहीं पहुंचा रहा है? लोकतंत्र मजबूत रहे इसके लिए समाज के सभी अंग स्वस्थ रहने चाहिए। दक्षिण भारत के कुछ नेताओं ने तमिल, कन्नड़, तेलुगू या मलयालम अस्मिता के साथ जोड़ कर हिन्दी विरोध की राजनीति निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ि कया। हिन्दी भाषा विरोधी राजनीति दक्षिण भारत के राज्यों की भाषाओं के संरक्षण, विकास, विस्तार और लोकतंत्र की स्थापना तथा संरक्षा के लिए भी हितकर नहीं रही है। एकात्म और संगठित भारत के लिए आवश्यक है कि देश में अन्य सभी भाषाओं के अस्तित्व के साथ ही हिन्दी का विकास, विस्तार और देश की संपर्क भाषा के रूप में पदस्थापित करना होगा। सत्ता की राजनीति भारत के लिए चुनौती न बने यह आवश्यक है।

## References

**[1]** Goldthwaite, R.A. (1995) Banks, Places and Entrepreneurs in Renaissance Florence, Aldershot, Hampshire, Great Britain, Variorum
**[2]** Macerich, George (30 June 2000), Central Banking – The Early years :- Others early Bank, issues in money and Banking, westport, connecticut, Praeger publishers. (Greenwood Publishing Group), P.42
**[3]** Thus by the 19 century we find – In ordinary cases of deposite of money with banking corporations,or banker's, the transaction amounts to a mere loan or mutuum, and the bank is to restore, not the same money, but an equivalent sum, whenever it is demonded." Joseph Story, Commentaries on the Law of Bailments (1832, P.66) and – "Money, when paid into a bank, ceases altogether to be the money of the prinicipal (see Parker V. Marchant, 1 Phillips 360), it is then the money of the banker, who is bound to return an equivalent by paying a similar sum to that deposited with him when he is asked for it," Lord Chancellor Cottenham, Foley v Hill (1848) 2 HLC 28.
**[4]** Rechards. The usual denomination was 50 or 100 Pounds, so these notes were not an everyday currency for the common people.
**[5]** A History of British Bank notes, british notes. co. uk.
**[6]** A short history of overdraft, account money, Archieved from the original on 2013/11/05.
**[7]** Fred Gottheil (1 Jan 2013), Principles of Economic Cengage Learning. P.417, Retrieved 11 Jan 2015.
**[8]** Santosh Kumar Das (1980). The Economic history of ancient India, cosmo publication, PP.229.
**[9]** Md Aquique (1974) Economic History of mithila, Abhinav Publication P. 157, Retrieved 12 Jan. 2015.
**[10]** Evolution of Paymant systems in India, Reserve Bank of India, 12 December 1998, Retrieved 12 Jan 2015.
**[11]** Radha Shyam Rungta (1970), The Rise of Business Corporation in India, 1851-1900, CUP Archive P-221.
**[12]** H.K. Mishra (1991) Famines and Povert in India, APH Publishing, p. 197, Retrieved 12 Jan 2015.
**[13]** Evolution of SBI, State Bank of India, Retrieved 12 Jan 2015.
**[14]** Business Financing Banks, Government of India, Retrieved 12 Jan 2015.
**[15]** History of Indian Banking System :- An Overview – "Jagranjosh" (News papers), 25 May 2017.
**[16]** Cooks Charles, Northcote (1863). The Rise Progress and Prensent Condition of banking India, Printed by P.M. Cranenburgh, Bengal Print.co, pp 177-200
**[17]** Shanker's weekly, 1974, pp 2,3, Retrieved 24 August 2017.
**[18]** History of Banking in India. (www.indianmoney.com), 25 September 2018.
**[19]** History of Banking in India in Brief (Before and After Independence)(www.gradeup.com), 17 Feb.2019
**[20]** Meaning of Banking (www.lopol.org).
**[21]** What is a bank, Introduction, Definition and Features of a bank. (www.bankall-info.org), 24 July 2018.
**[22]** Bank. (www.businessdictionary.com).
**[23]** Auten v United States National Bank 174 US 125, Published at https://attlaw.org/v1/eases/388326.
**[24]** Re shields Estate (1901) IRISH Reports 182.
**[25]** Joachimson v Swiss bank Corporation 1921, All ER92 and at 3, KB 110.
**[26]** Structure of Banking Sector in India – "Jagran Josh" (News paper), 1 April 2019, Author :- Hemant Singh.
**[27]** Reserve Bank of India Act 1934 (As modified up to 27 Feb. 2009), PDF, Reseve bank of India. Retrieved 20 Nov. 2010.
**[28]** RBI History – Reserve bank of India Nationalisation Newspaper Clipping.
**[29]** Shaktikant Das is new governor of RBI, United News of India. 11 December 2018, Retrieved 11 December 2018.
**[30]** Different Types of Bank in India :- Explained – "Livemint" (www.livemint.com), 16 Sept. 2015.
**[31]** Banking. (www.paisabazaar.com).
**[32]** Structure of Banking system in India. (www.gradeup.com), 27 Feb.2019, Author :- Neeraj Mishra.
**[33]** Foreign Banks in India. (www.gktoday.in)
**[34]** Conference of Principal code compliance officers (Pccos)/chairmen of Regional Rural Banks organised by BCSBI at Mumbai, on July 15, 2013. Archived from the original on 24 july 2013.
**[35]** Merger of Regional Rural Banks within same state likely – (www.economictimes.com) 27 Feb. 2019. Author :- Dheeraj Tiwari.

**[36]** Fortune, Global 500 List, Retrieved 22 May 2018.
**[37]** Away from the public Gaze, State bank of India is preparing to unleash a revolution Retrieved 22 May 2018.
**[38]** State Bank of India. (www.paisabazaar.com)
**[39]** Annual Report 2018-19 of State Bank of India.
**[40]** Cooperative bank in India. (www.gktoday.in), 14 March 2015.
**[41]** RBI Issues Find Norms for Payment and Small Finance Bank, Zee News, 28 November 2014, Retrieved 8 March 2015.
**[42]** Guidelines for Licencing of Small finance Bank in the private sector, Reserve bank of India. Retrieved 8 March 2014.
**[43]** Operating Guidline, for payment Bank (PDF) Reserve Bank of India, 6 October 2016, Retrieved 12 August 2019.
**[44]** RBI oppoints committee on comprehensive Financial Services for small businesses and Low Income Households" Reserve bank of India. 23 September 2013, Archieved from the orginal on 2 April 2015.
**[45]** RBI Panel suggest new set of bank for Financial Inclusion, "Live Mint," 7 Jan. 2014.
**[46]** RBI Releases Draft Guidelines for Licencing of Payments Banks and Small Banks, Reserve bank of India. 17 July 2014, Retrieved 2 March 2015.
**[47]** RBI Releases Guidelines for Licencing of Payment Banks, Reserve Bank of India, 27 Nov. 2015.
**[48]** Banking sector in India. (www.ibef.org) June 2019.
**[49]** Indian banking Industry Analysis. (www.ibef.org) August 2019.
**[50]** जन धन खाते में १०,००० ओवर ड्राफ्ट सुविधा का मतलब क्या हैं - ''Economic Times" (News paper) 26 July 2019.
**[51]** PSB loan sin 59 minutes.com emerges Largest Fintech Lending platform – "G.K.Today" 4 March 2019.
**[52]** Mudra Load – (www.rappev.com) 16 October 2018.
**[53]** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कैसे मिल सकता हैं लॉन - ''Economic Times" (News paper), 26 July 2019.
**[54]** सार्वजनिक क्षेत्र के १२ बैंकों में ४८२३६ करोड़ रूपये निवेश करेगी सरकार. (www.livehindustan.com)२० फरवरी २०१६
**[55]** Banking Crises :- An Indian history – (www.livemint.com) 26 Feb 2018.
**[56]** The Status of Public Sector Bank in India. (www.livemint.com) 24 August 2018.
**[57]** भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की विफलता के पीछे क्या कारण हैं। (www.rediff.com) 10 March 2015.
**[58]** बाहरी हरदेव, हिन्दी भाषा व्याकरण
**[59]** पाण्डेय मैनेजर, भाषा और भूमंडलीकरण, शब्द संधान प्रकाशन, नई दिल्ली।
**[60]** www.vistawide.com
**[61]** बसु डा० डीडी, भारत का संविधान, वाधवा प्रकाशन ऐंड कं० नागपुर
**[62]** पाण्डेय कैलाशनाथ, लेख, मीडिया विमर्श, मार्च २०११
**[63]** अध्ययन सामग्री, पीजीडीजेएमसी, यूपीआरटू
**[64]** दैनिक जागरण, अंतर्राष्ट्रीय पेज, २१.७.२०१३
**[65]** उपाध्याय रमेश व उपाध्याय संध्या, भाषा और भूमंडलीकरण, शब्द संधान प्रकाशन, नई दिल्ली
**[66]** जोशी रामशरण, मीडियाः मिशन से बाजारीकरण तक, मीडिया विमर्श, मार्च २०११
**[67]** राजकिशोर, लेख, पत्रकारिता की भाषा, गूगल डॉट काम
**[68]** कुमकुम संगारी, भाषा का जनपक्षीय परिप्रेक्ष्य
**[69]** राजकिशोर, लेख, पत्रकारिता की भाषा, गूगल डॉट काम
**[70]** अध्ययन सामग्री, पीजीडीजेएमसी, यूपीआरटू
**[71]** वैदिक डा० वेद प्रताप, लेख, भाषाई गुलामी में भारत सबसे आगे, kranti4people.com, २१.११.२०११
**[72]** पाण्डेय रतन कुमार, मीडिया की भाषा, समकालीन माध्यम, जनवरी २०१३, समय, समाज और मीडिया पर एकाग्र विशेषांक, पृष्ठ १७६
**[73]** दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज
**[74]** गांधी, मोहनदास करमचंद, राष्ट्रभाषा और लिपि, २० अक्टूबर १६१७ के गुजरात भाषण का अंश,
**[75]** http//blog.mygov.in/editorial, 14.09.17, page seen 22.10.18
**[76]** बसु, डा० दुर्गा दास, भारत का संविधान, वाधवा एण्ड कं० नागपुर, पेज ३८७
**[77]** www.aajtak.in , seen 10.01.2019
**[78]** सिंह नीरज भाषा की राजनीति का गढ़ है तमिलनाडु,, www.chauthiduniya.com, 23.10. 2013, seen 4.02.2019
**[79]** www.wikipedia.org, seen 12.01.2019
**[80]** वैदिक डा० वेद प्रताप, दक्षिण का हिंदी विरोध कैसे खत्म हो?, www.nayaindia.com, 27.07.2017, seen 23.01.2019
**[81]** www.dailyhunt.in, seen 08.02.2019

**[82]** आनंदी एस., विजय भास्कर, www.thewirehindi.com
**[83]** निश्चल डा० ओम, हिन्दी पर अंग्रेजी की प्रेत छाया, गर्भनाल ई पत्रिका, जनवरी २०१९,
**[84]** दास अरविंद, भूमंडलीकरण के दौर में हिन्दी, www.bargad.org, seen 25.12.2018
**[85]** दाधीच, बालेन्दु शर्मा, तकनीकी विकास से समृद्ध होगी हिन्दी, लेख, पांचजन्य डॉट कॉम, २८.०८.१८, १०.११.१८
**[86]** कर्नाटक में हिन्दी बर्दाश्त नहीं , www.aajtak.indiatoday.in, 22.08.2017, seen 08 feb. 2019